नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 071
दि. 13.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

देशभर में रक्षा भूमि पर अतिक्रमण और उसकी संवेदनशीलता: संसद में खुलासा

11,152 एकड़ जमीन पर कब्जा, सुरक्षा और रणनीतिक इस्तेमाल पर सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में फैली लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से 11,152 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, जबकि 8,113 एकड़ भूमि विभिन्न कानूनी विवादों में फंसी हुई है। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संसद में दी। उन्होंने बताया कि कुल 18 लाख एकड़ भूमि में से 45,906 एकड़ अतिरिक्त श्रेणी में रखी गई है, जो सेना की तत्काल आवश्यकता से अधिक है और जिसे अन्य केंद्रीय विभागों को सौंपा जा सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही कुछ भूमि खाली दिखाई देती हो, लेकिन उसकी रणनीतिक और सैन्य उपयोग के लिए भविष्य में आवश्यकता बनी रह सकती है, जैसे कि प्रशिक्षण, मोबिलाइजेशन ड्रिल, KLP प्लान और मैरिड अकोमोडेशन।

रक्षा भूमि पर अतिक्रमण और कानूनी विवाद की स्थिति गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण वाली जमीन पर कई बार स्थानीय लोगों और गैरकानूनी कब्जेदारों का कब्जा पाया गया है। इसके साथ ही 8,113 एकड़ भूमि के मामले में न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिनमें जमीन के मालिकाना हक, सरकारी दस्तावेज़ों की अदला-बदली, पुराने अधिग्रहण मामलों और स्थानीय दावों से जुड़े विवाद शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की अतिक्रमण घटनाओं का समय पर समाधान न होने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि कई भूमि ऐसे इलाकों में हैं जो रणनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं।

संसद में यह सवाल भी उठाया गया कि रक्षा भूमि अधिग्रहण या बेदखली अभियानों के दौरान

ग्रामीण और स्थानीय समुदायों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। सरकार ने इस पर स्पष्ट किया कि अभी तक इसका कोई औपचारिक आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिया कि यदि निजी भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यह है कि सैन्य जरूरतों के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय किसी प्रकार का सामाजिक या आर्थिक नुकसान न्यूनतम हो।

रक्षा मंत्रालय के बजट पर भी संसद में चर्चा हुई। सवाल यह उठाया गया कि क्या धीमी खरीद की प्रक्रिया के कारण 12,500 करोड़ रुपये वापसी की गई। इस पर राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। संशोधित बजट का पूरा उपयोग किया जा चुका है और आगे के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया को और तेज तथा पारदर्शी बनाने के लिए DAP (Defence Acquisition Procedure) में प्रस्तावित संशोधन लागू किए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे न केवल सैन्य तैयारियों में तेजी आएगी बल्कि रणनीतिक उपकरणों और रक्षा संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। विशेषज्ञ और सुरक्षा विश्लेषक मानते हैं कि यह रिपोर्ट न केवल रक्षा भूमि की स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है बल्कि इस बात का भी संकेत देती है कि प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करना कितना जरूरी है। रक्षा भूमि पर अतिक्रमण का मामला केवल स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील है। अतिक्रमण की रोकथाम और कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ अतिरिक्त भूमि के उपयोग का स्पष्ट रोडमैप तैयार करना भविष्य की सैन्य तैयारियों और रणनीतिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। सरकार ने यह भरोसा भी दिलाया कि आने वाले वर्षों में भूमि उपयोग की समीक्षा, कानूनी विवादों का निपटारा और अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया नियमित रूप से की जाएगी। साथ ही, रक्षा खरीद और संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए DAP के संशोधनों को लागू किया जाएगा। यह कदम देश की सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों को मजबूत करने के साथ-साथ अतिक्रमण के खिलाफ सख्त संदेश देने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर करती है। रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया में सुधार, स्थानीय समुदायों के हितों की सुरक्षा और सेना की रणनीतिक जरूरतों का संतुलन बनाए रखना अब पहले से भी अधिक जरूरी हो गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त भूमि का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करेगा और भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित खतरे का सामना करने में सहायक होगा।

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव: 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के पहले चरण के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्यभर में 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। यह संख्या न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम मानी जा रही है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी गहरे होते जा रहे हैं। खास बात यह है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई गढ़ों में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं, जिससे विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में इस सीट पर कुल 1,61,509 मतदाता दर्ज थे, जिनमें से 44,787 नाम अब हटा दिए गए हैं। यह आंकड़ा विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से चार गुना से भी ज्यादा है। नंदीग्राम में जहां कुल 2,78,212 मतदाता थे, वहां से 10,599 नाम हटाए गए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सियासी हलकों में यह

बहस तेज हो गई है कि आखिर शहरी इलाकों और सत्ताधारी दल के प्रभाव वाले क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में नाम क्यों कटे। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो साउथ 24 परगना जिला सबसे ऊपर रहा है, जहां से 8,16,047 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। यह वही जिला है जिसे तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से उन्होंने पिछले चुनाव में सात लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में इस जिले से इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने को राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। कोलकाता शहर के कई विधानसभा क्षेत्रों में भी भारी कटौती हुई है। राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ कोलकाता की चौरंगी सीट से हटाए गए, जहां 74,553 मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं। इस सीट का प्रतिनिधित्व तृणमूल कांग्रेस की विधायक नयना बंद्योपाध्याय करती हैं। कोलकाता पोर्ट क्षेत्र से 63,730 नाम हटाए गए, जहां से वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम विधायक हैं। इसके अलावा टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व मंत्री अरूप बिस्वास करते हैं, वहां से 35,309 नाम काटे गए। दूसरी ओर, सबसे कम नाम बांकुरा जिले के कोतुलपुर विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए, जहां यह संख्या 5,678 रही। यह तस्वीर सिर्फ तृणमूल के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। भाजपा के प्रभाव वाले इलाकों में भी बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। आसनसोल साउथ विधानसभा क्षेत्र, जहां से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल जीतकर आई थीं, वहां 39,202 नाम हटाए गए हैं। वहीं सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा विधायक शंकर घोष करते हैं, वहां से 31,181 नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया किसी भी दल विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के उद्देश्य से की गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समयसीमा में भी बदलाव किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में अब 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में यह तारीख 26 दिसंबर तय की गई है, जबकि गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समयसीमा पूरी हो चुकी है और इन राज्यों के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। केरल में पहले ही अंतिम तारीख 18 दिसंबर तय की जा चुकी है, जहां ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को जारी होगी।

55 साल का 'कुंवारा' दूल्हा, चार शादियों का खुलासा: लाखों की ठगी और फर्जी पहचान का सनसनीखेज मामला

(जीएनएस)। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने अहमदाबाद से एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को कुंवारा बताकर चार महिलाओं से शादी की और लाखों रुपए तथा जेवर ठग लिए। गिरफ्तार आरोपी बिरेन कुमार सोलंकी 55 वर्ष का है, लेकिन इस उम्र में भी उसने अपने बच्चों और पिछली शादियों को छुपाकर महिलाएँ फंसाई। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उसके तीन बड़े बच्चे हैं, जिनकी उम्र 35, 27 और 25 साल है, फिर भी उसने महिलाओं को अपने अविवाहित होने का भ्रम देकर शादी की।

मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब दुर्ग की एक महिला टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका बिरेन कुमार के साथ चार साल का लिव-इन संबंध रहा, और 2023 में शादी हुई। शादी के समय बिरेन अकेला गुजरात से आया और बारात न लाने का बहाना बनाकर महिला को भ्रमित किया। शादी के बाद बिरेन ने शिक्षिका से 32 लाख रुपये और 12 लाख रुपये

के जेवर ऐंठ लिए।

जांच में यह सामने आया कि बिरेन पहले भी कई महिलाओं से शादी कर चुका था। साल 2019 में उसने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर विज्ञापन देकर शिक्षिका से संपर्क किया और खुद को अविवाहित तथा प्राइवेट कंपनी में उच्च पदाधिकारी बताया। मुलाकातों और एक साल के भीतर शादी के निर्णय के बाद शिक्षिका दुर्ग लौट आईं। इसके बाद बिरेन ने शादी से पहले लिव-इन में रहने का बहाना बनाकर तीन साल तक उन्हें अपनी पिछली शादियों और परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

3 मई 2023 को दुर्ग के एक होटल में शादी हुई। शादी के बाद बिरेन ने शिक्षिका को अपने पैतृक घर या रिश्तेदारों से नहीं मिलवाया। इसके बजाय वह अलग घर में उन्हें रखकर घर खरीदने, EMI, किस्त और गोल्ड लोन जैसी बातों का बहाना बनाकर लाखों रुपए हड़पता रहा। जानकारी के अनुसार, शिक्षिका से तीसरी शादी करने के केवल एक महीने बाद, जून 2023 में बिरेन ने गुजरात की एक सरकारी डॉक्टर से चौथी शादी भी कर ली। इस दौरान शिक्षिका को बिरेन की पहली दो शादियों और तीन बच्चों का भी पता चला।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि बिरेन का केवल एक ही पत्नी के साथ तलाक हुआ था। पीड़ित महिला ने बताया कि जब भी उन्होंने पैसों की मांग की तो बिरेन गाली-गलौच करते हुए कहता कि उनका कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस ने आरोपी का असली नाम दिलीप सिंह झाला बताया, जबकि उसके आधार कार्ड और वोटर कार्ड अलग-अलग नामों पर बने पाए गए। मोहन नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल, मामले में आगे की कार्रवाई और ठगी गई राशि की वसूली के प्रयास जारी हैं, जिससे यह मामला पूरे देश में फर्जीवाड़े और शादी के नाम पर ठगी की चेतावनी के रूप में चर्चा में है।

सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन मामलों में अधकचरी रिपोर्टिंग पर जताई गंभीर चिंता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चिंता जताते हुए कहा कि न्यायालय किसी भी तरह की पब्लिसिटी या मीडिया में बने नैरेटिव से प्रभावित नहीं होता, लेकिन विचाराधीन मामलों पर अधकचरी और विकृत रिपोर्टिंग जनमानस को भ्रमित कर सकती है, जो न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता और विश्वास के लिए गंभीर खतरा है।

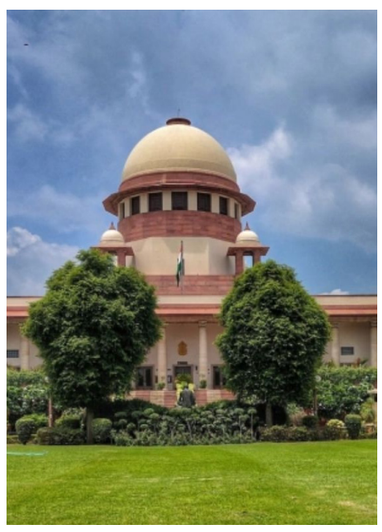

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वापसी का मामला शामिल था जिन्हें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना 27 जून को बांग्लादेश भेज दिया गया था। यह परिवार लगभग दो दशक से दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था और उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में 18 जून को हिरासत में लिया गया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि सुनाली खातून, जो गर्भवती हैं, अपने बेटे के साथ भारत लौट आई हैं। पीठ ने केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र ने निर्वासन से पहले 30 दिन तक अनिवार्य जांच नहीं की, जबकि गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जांच करना आवश्यक था।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अत्यधिक उत्साह में किए गए निर्वासन कदम न्यायिक माहौल के लिए हानिकारक हैं और इससे न्यायपालिका की प्रक्रिया और आम जनता के विश्वास पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर जोर दिया कि मीडिया और नागरिकों को संवेदनशील मामलों में तथ्यों और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में गलत या अधकचरी रिपोर्टिंग न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है और समाज में भ्रम फैलाने का काम कर सकती है।

इस मामले ने एक बार फिर यह याद दिलाया कि न्यायिक मामलों में जिम्मेदार और संतुलित रिपोर्टिंग ही लोकतंत्र और न्यायपालिका के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील मामलों में पूरी सावधानी और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता और मीडिया को सही जानकारी मिले और कोई भ्रांति उत्पन्न न हो।

अहमदाबाद के होटल में आग, 35 लोग सुरक्षित बचाए गए; होटल मैनेजर फरार

(जीएनएस)। अहमदाबाद के सोला इलाके में शुक्रवार दोपहर को एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। साइंस सिटी रोड पर स्थित परिश्रम एलिगेंस व्यावसायिक परिसर की दूसरी मंजिल पर स्थित होटल सिटीजन इन में दोपहर लगभग तीन बजे अचानक आग लग गई। दमकल और सुरक्षा अधिकारियों की तत्पर कार्रवाई से होटल में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

अग्निशमन केंद्र के अधिकारी प्रवीणसिंह सोलंकी ने बताया कि आग पर एक घंटे के भीतर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर आठ से नौ दमकल गाड़ियाँ भेजी गई थीं। दमकलकर्मियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर और सीढ़ियों का इस्तेमाल करके इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला। अधिकारी इस बात की भी पुष्टि कर चुके हैं कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और इसकी जांच जारी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग होटल की पेंट्री में लगी थी, जहां फ्रिज, गैस स्टोव और सिलेंडर रखा हुआ था। आग लगने के तुरंत बाद होटल का मैनेजर अनिल पटेल कथित तौर पर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, अनिल पटेल राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए तुरंत तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के समय होटल में कई पर्यटक और कर्मचारी मौजूद थे। आग लगते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन दमकल कर्मियों की तेजी और सुरक्षित निकासी की वजह से कोई भी गंभीर चोटिल नहीं हुआ।

पुलिस और फायर विभाग ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच में पाया गया कि होटल में सुरक्षा प्रोटोकॉल और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया गया था। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच के बाद मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने होटल उद्योग में अग्नि सुरक्षा और सतर्कता के महत्व को एक बार फिर उजागर कर दिया है। फिलहाल, होटल में सभी फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और आग की पूर्ण निगरानी जारी है। होटल मैनेजर की गिरफ्तारी और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच जारी रहने के कारण अधिकारियों ने आम जनता से होटल के पास जाने से बचने की सलाह दी है।

संपादकीय

सोशल मीडिया प्रतिबंध की आस्ट्रेलियाई पहल

पश्चिमी देश, जिस सोशल मीडिया के गुणगान करते नहीं अघाते थे, अब उन्हें इससे बच्चों में पनपती विकृतियों की हकीकत समझ में आने लगी है। सुगबुगाहट तो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक प्रतिबंधों को लेकर हो रही है, लेकिन इस दिशा में पहल करने का साहस आस्ट्रेलिया ने सुधारवादियों के दबाव में उठाया है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार इसलिए वापस ले रहे हैं ताकि बच्चों के बच्चे होने के अधिकार और माता-पिता की मानसिक शांति के अधिकार की रक्षा हो सके। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि यह सुधार जिंदगियां बदल देगा। साथ ही आस्ट्रेलिया के बच्चों को बचपन जीने का मौका देगा। आज दुनिया के तमाम देश मंथन कर रहे हैं यदि आस्ट्रेलिया यह पहल कर सकता है तो वे क्यों नहीं कर सकते। इनमें वे तमाम अभिभावक भी शामिल हैं जो अपने बच्चों की आत्महत्या के लिये सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलिया में यदि सोशल मीडिया मंच 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाने में असफल रहते हैं, तो उन्हें करीबन पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना चुकाने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है। आस्ट्रेलियाई सरकार क्रिसमस तक मूल्यांकन करेगी कि ये प्रतिबंध कितने कारगर साबित हुए हैं। निस्संदेह, आस्ट्रेलिया की पहल ने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखने की मुहिम को नई ऊर्जा दे दी है। कमोवेश, भारत जैसे देश भी सोशल मीडिया की असामाजिकता का दंश झेल रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ ऑनलाइन बुलिंग से लेकर ऑनलाइन ठगी तक के तमाम मामले गाहे-बगाहे सामने आते रहते हैं। विडंबना है कि आज सोशल मीडिया पर प्रसारित वयस्कों की सामग्री से बच्चे जाने-अनजाने में परिचित हो रहे हैं। वे समय से पहले वयस्क हो रहे हैं। जिससे समाज में तमाम तरह की सामाजिक विकृतियां पैदा हो रही हैं। निस्संदेह, इससे आने वाले समय में घातक सामाजिक विद्रूपताएं पैदा हो सकती हैं। दरअसल, बच्चों के लगातार घंटों कथित सोशल मीडिया में सक्रिय रहने से उनमें तमाम शारीरिक व मानसिक विसंगतियां पैदा हो रही हैं। उन्हें संस्कार अब माता-पिता व शिक्षक नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दोहन करने वाले निहित स्वार्थी तत्व दे रहे हैं। जो कि भारतीय जीवन-मूल्यों व संस्कारों से मेल नहीं खाते। आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इतनी अश्लील व द्विअर्थी सामग्री का प्रवाह है कि हमारे किशोर आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। सोशल मीडिया के घातक प्रभाव के चलते आज बच्चों के नायक बदल गए हैं। उनके आदर्श बदल गए हैं। उनका नजरिया बदल रहा है। सोशल मीडिया के कतिपय मंचों पर अश्लील सामग्री की उपलब्धता ने किशोरों में ब्रह्मचर्य के भारतीय मूल्यों को ताक पर रख दिया है। विडंबना यह है कि घंटों सोशल मीडिया पर बैठे रहने वाले बच्चे शारीरिक सक्रियता से दूर हो रहे हैं। जिससे उनमें मोटापा व अनेक गैर संक्रामक रोग पनप रहे हैं। वे किशोर अवस्था में मधुमेह आदि उन रोगों के शिकार बन रहे हैं जो कभी बड़ी उम्र के लोगों को हुआ करते थे। इस संकट का एक घातक पहलू यह भी है कि मोबाइल पर लगातार सोशल मीडिया के कार्यक्रम स्क्रॉल करने वाले बच्चों की मानसिक एकाग्रता बाधित हो रही है। जाहिर है इसका प्रभाव उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर पड़ेगा। एक समय दुनिया के तमाम देशों में जिन भारतीय प्रतिभाओं का डंका बजता था, शायद भविष्य में ऐसा न हो। घंटों सोशल मीडिया पर बिताने वाले छात्रों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अपनी पढ़ाई के लिये पूरी तरह एकाग्र हो सकेंगे। निरंतर कल्पना लोक में विचरण करने वाले बच्चे जब जीवन की हकीकत से जूझते हैं तो टूटने-बिखरने लगते हैं। गाहे-बगाहे आत्महत्या करने वाले किशोरों के डेटा का यदि गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो निश्चित रूप से हम सोशल मीडिया के घातक प्रभाव की हकीकत से रूबरू हो सकते हैं। आस्ट्रेलियाई पहल से सबक लेकर भारत के नीति-नियंताओं को भी इस दिशा में गंभीरता से पहल करनी चाहिए। इस दिशा में थोड़ी भी देरी की देश को भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

देश की राजधानी किसी बुरे सपने से कम नहीं है

> "सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस—पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है।

देश में वोट बैंक की राजनीतिक के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे हाशिए पर धकेले जाते रहे हैं। राजनीतिक दल इसे समस्या तो मानते हैं किन्तु इसके स्थायी निदान के लिए न तो कोई कार्ययोजना है और न ही इच्छाशक्ति। देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र भीषण प्रदूषण की मार झेल रहा है। यही वजह है कि प्रदूषण की भयावहता तमाम क्षेत्रों में तरक्की को मुंह चिढ़ा रही है। सरकारों और राजनीतिक दलों की बला से प्रदूषण प्रभावित इन क्षेत्रों के करोड़ों लोगों बेशक तिल—तिल करके मरते रहें। इसके विपरीत नेताओं का सरोकार सिर्फ चुनाव जीतने भर तक सीमित रह गया है। सत्तारुढ़ और विपक्षी दल इस मुद्दे पर चिंता जताने तक सीमित हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपने चेहरों पर मॉस्क लगाया और प्रदूषण के खिलाफ नारे लिखे तख्वियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। एक बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी जिस पर लिखा था 'मौसम का मजा लीजिए'। सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस—पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। दिल्ली का औसत एक्यूआई लेवल 377 तक दर्ज हो चुका है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या देखने को मिल रही है। आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक जहांगीर पुरी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नेहरू नगर में एक्यूआई लेवल 400 के पार तक पहुंच गया। दिल्ली की हवा में घुला जहर कम कब होगा। इस सवाल का जवाब इस समय शायद किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए डॉक्टरों

ने साफ कह दिया है कि बच्चों की सेहत ठीक रखना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए।

दिल्ली में एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारण ट्रांसपोर्ट, पराली है। गाड़ियों से फैले प्रदूषण का हिस्सा 18.42% था। आंकड़ों के हिसाब से 16.31% प्रदूषण के अन्य सोर्स हैं, जिसमें आतिशबाजी, डीजल जनरेटर जैसे सोर्स शामिल है। शादियों के सीजन की वजह से आतिशबाजी हो भी रही हैं। अगले तीन दिन इन अन्य सोर्स का प्रदूषण का हिस्सा और बढ़कर 43.4% तक जाने का अनुमान है। दिल्ली में एक्यूआई 400 तक के खतरानक स्तर को छू चुका है, जो वायु प्रदूषण की गंभीर हालत दिखाता है। वहीं मुंबई में भी ये 200 के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद वहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप 4) लागू किया गया। हालांकि दिल्ली में अभी ग्रैप 4 लागू नहीं किया गया। उल्टे दिल्ली एनसीआर में 26 नवंबर को ग्रैप 3 की पाबंदियां भी वापस ले ली गई थीं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शहर में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। देवनार, मलाड, बोरीवली, अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पवई और मुलुंड जैसे इलाकों में प्रदूषण की खराब स्थिति के बाद ये फैसला लिया गया था।

दिल्ली में प्रदूषण पराली जलने, वाहनों के धुएं और कारखानों से निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार है। हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से हालात और खराब हो जाते हैं। हालांकि मुंबई और अन्य समुद्री इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहतर रहती है, क्योंकि वहां हवा चलने के कारण प्रदूषणकारी तत्व शहर से दूर चले जाते हैं। मुंबई में मेट्रो, फ्लाईओवर जैसे बड़े निर्माण कार्य, वाहनों की बढ़ती तादाद और कचरा जलाने जैसी वजहों से हालत बिगड़ी है। मुंबई जैसे समुद्री इलाकों में एक्यूआई बढ़ना खतरे की घंटी है। मुंबई में ग्रैप-4 की पाबंदियों के बाद एक्यूआई 150 से नीचे आ गया, जबकि दिल्ली की हवा में अब भी दम घुट रहा है। मुंबई की हवा अब सांस लेने लायक हो गई है। यहां कई जगह एक्यूआई लेवल 100 के आसपास हो गई। हालांकि, दिल्ली में एक्यूआई लेवल अब भी कई जगह 400 के पार है। हवा की गति बढ़ने और पानी छिड़काव जैसे उपायों से मुंबई में हवा की गति बढ़ने और पानी छिड़काव जैसे उपायों से मुंबई में एक्यूआई स्तर 150 से नीचे आने में मदद मिली।

दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था आईक्यूएआईआर की नवीनतम लाइव रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली इस सूची में पहले स्थान पर रही। जबकि दूसरे स्थान पर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद 251 के एक्यूआइ के साथ दर्ज है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर (एक्यूआइ 215), चौथे पायदान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका 211, एक्यूआइ के साथ है। भारत का कोलकाता भी 211 के एक्यूआइ के साथ पांचवें स्थान पर है। देश की राजधानी दिल्ली में एयर इमरजेंसी है। राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बन गई है। राजधानी दिल्ली हांफ़ रही है, खांस रही है। दिल्ली की हवा ज़हरीली हो गई है। दिल्ली में हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में ज़हर भर रहा है। दिल्ली को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। दिल्ली-एनसीआर इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान बन गई है। देश ही नहीं दुनिया भर के अख़बारों-समाचार चैनलों, वेबसाइट्स में दिल्ली की हवा सुर्ख़ियों में है। दिल्ली एनसीआर में इस समय धुंध नहीं बल्कि, हवा में मौजूद धूल के कारण है, वो धूल जो कभी कंस्ट्रक्शन की वजह से कभी पोल्यूशन की वजह से कभी पराली की वजह से घटना हो रही है।

ये लटके हुए कण जो धूल के हैं ये पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे महीन कण इसमें शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि एक दिन की दिल्ली की हवा में सांस लेना करीब 50 सिगरेट के पीने के बराबर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की हवा का क्या हाल है। रोज पीने-उपयोग करने वाला भूजल भी अब दिल्ली में सुरक्षित नहीं बचा है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड की नई रिपोर्ट बताती है कि इस पानी में यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्वों के साथ नाइट्रेट, फ्लोराइड, लेड और ज्यादा नमक तक मिला हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि राजधानी के कई हिस्सों से लिए गए भूजल के नमूनों में यूरेनियम की मात्रा सामान्य सीमा से कहीं अधिक पाई गई। यूरेनियम धीरे-धीरे शरीर में जमा होता है और गुर्दों, हड्डियों और शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है।

रिपोर्ट में साफ हुआ कि पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड, लेड और ज्यादा नमक भी पाया गया है। नाइट्रेट ज़्यादातर गंदे पानी और खाद से जमीन में रिसकर आता है। फ्लोराइड बढ़ने से दाँत और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। लेड शरीर के दिमागी विकास पर भारी असर डालता है और बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। नमक और घुले पदार्थ ज्यादा होने से पानी पीने लायक नहीं रह जाता और पाचन व गुर्दों पर दबाव पड़ता है। दिल्ली में लगातार ज़्यादा गहराई तक बोरिंग होने लगी है, जिससे ऐसे हिस्सों का पानी ऊपर आ रहा है जहाँ मिट्टी में खुद ही खनिज और भारी तत्व मौजूद रहते हैं। दूसरी ओर, सीवर रिसाव, गंदे पानी का जमीन में घुसना और रासायनिक कचरे का सही निस्तारण न होना भी भूजल को ज़हरीला बना रहा है। जमीन रिचार्ज होने की जगह घट गई है और पानी अपना प्राकृतिक संतुलन खो रहा है।

दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण भी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और यमुना में झाग भी बनने लगते हैं। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में सफेद झाग दिखाई दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह झाग पानी में मौजूद फॉस्फेट, डिटर्जेंट और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण बनता है। यह न सिर्फ नदी के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। सवाल यही है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली वायु—जल प्रदूषण को लेकर और कितनी रसातल तक जाएगी। आखिर नेताओं और सरकारों की कुंभकर्णी नींद कब खुलेगी। चुनी हुई सरकारों से उम्मीद की जाती है कि जनहित का ख्याल रखेंगी। इस लिहाज से दिल्ली किसी बुरे सपने से कम नहीं है।

प्रेरणा

मन की अशांति से आत्मा की शांति तक एक

वॉल्टेयर के जीवन के दिनों में एक सुबह आसमान हल्का-सा सुनहरा हो उठा था। शहर की गलियों में सर्द हवा बह रही थी, और उसी हवा को चीरते हुए एक युवा विद्वान उनकी ओर बढ़ चला। उसके कदम तेज़ थे, पर मन भीतर से उलझा हुआ था। आंखों में बेचैनी थी, माथे पर प्रश्नों की लकीरें। वह ज्ञान की तलाश में था, पर ज्ञान का भार ही उसके भीतर अशांति बनकर बैठ गया था।

वॉल्टेयर अपने घर के बाहर पत्थरों की बनी पुरानी बेंच पर बैठे थे, जहाँ सुबह की धूप झरनों की तरह छनकर गिरती थी। युवा उनके सामने आकर ठहर गया। उसकी आवाज़ काँपी—"सर, मैं दुनिया को समझना चाहता हूँ, और जितना पढ़ता हूँ, उतना ही उलझता जाता हूँ। मेरे भीतर शोर बढ़ गया है। क्या सच में इस विशाल दुनिया को समझ पाना संभव है?"

वॉल्टेयर ने उसकी आँखों में एक क्षण देखा—उस अशांति को जो हर युग में किसी न किसी खोजी के भीतर जन्म लेती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान के साथ हाथ के इशारे से उसे अपने साथ चलने को कहा।

घर के पिछवाड़े पहुँचते-पहुँचते हवा और शांत हो गई थी। वहाँ एक छोटा-सा बाग था, पर बाग़ की अपनी चुप्पी में एक अनोखी वाणी छिपी हुई थी। कुछ पौधे ऊँचे खड़े थे, कुछ झूल रहे थे, कुछ की पत्तियाँ झरने लगी थीं। पर पूरा बाग़ एक सहज लय में साँस ले रहा था।

वॉल्टेयर मिट्टी पर झुके और बड़ी कोमलता से

उसे छूते हुए बोले—"तुम्हें यहाँ क्या दिखता है?"

युवक ने चारों ओर देखा—"कुछ पौधे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, पर कुछ तो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं।"

वॉल्टेयर ने उसकी ओर देखा—"अब ज़रा यह बताओ, क्या इस बाग़ ने कभी शिकायत की कि एक फूल कम है? क्या हवा ने कभी कहा कि कुछ पत्ते पीले हैं? क्या मिट्टी यह सोचती है कि उसे हर पौधे को बराबर सुंदरता देनी चाहिए?"

युवा चुप हो गया। पहली बार उसने उस बाग़ को अलग नज़र से देखा—एक ऐसे जीवित शिक्षक की तरह, जो बिना बोले सब सिखा रहा था।

वॉल्टेयर ने आगे कहा—"ज्ञान भी ऐसा ही बाग़ है। तुम उसे एक दिन में पूरा खिला नहीं सकते। तुम उसे चाहकर भी एक क्षण में समझ नहीं सकते। अगर तुम हर विचार, हर सूचना, हर पुस्तक को एक साथ अपने भीतर भरने की कोशिश करोगे, तो मन बोझ से दब जाएगा। जैसे पौधे को एक ही दिन सौ बाल्टियाँ पानी दे दो, तो वह मर जाएगा। ज्ञान भी उसी तरह मर जाता है—अति से, जल्दबाज़ी से, अधैर्य से।"

युवा धीरे-धीरे बाग़ की पगडंडी पर चलते हुए सब समझने लगा था। उसकी चाल अब पहले जैसी बेचैन नहीं थी।

वॉल्टेयर ने उसकी ओर मुड़कर कहा—"तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम दुनिया को नहीं समझते। समस्या यह है कि तुम उसे एक ही बार में समझ लेना चाहते हो। दुनिया विशाल है—तुम्हें उसकी पूरी तस्वीर एक ही क्षण में नहीं दी जा सकती। पर तुम्हें उसका एक छोटा-सा अंश समझने को हर दिन दिया जा सकता है। यही जीवन का नियम है—जो तुम्हारे हाथ में है, उसे संवारो। जो नहीं है, उसे जाने दो। जो तुम्हारी समझ में आज नहीं आता, वह कल समझ आएगा, पर उसे बलपूर्वक आज भीतर डालने की कोशिश मत करो।"

धीरे-धीरे युवक की आँखों का धुंधलापन साफ होने लगा। उसके चेहरे पर एक शांत, गहरा प्रकाश उतर आया था। उसने महसूस किया कि समझ उतनी ज़रूरी नहीं होती, जितना कि समझने का धैर्य।

वॉल्टेयर कुछ कदम आगे बढ़े, हवा में बहते पत्तों को देखते हुए बोले—"धैर्य एक प्रकाश है। वह तेज़ नहीं होता, पर अंधेरे को धीरे-धीरे मिटा देता है। जिसने धैर्य पा लिया, उसने दुनिया को समझने का आधा रास्ता पा लिया। दुनिया को समझने की जल्दी मत करो, बस उसके साथ चलना सीखो—धीरे, संतुलित, और शांत होकर।"

युवक वॉल्टेयर के चरणों में झुक गया। वह पहली बार सच में हल्का महसूस कर रहा था—मानो मन के भीतर का कोलाहल किसी दूर के जंगल में खो गया हो।

वह यह समझ चुका था कि ज्ञान अचानक बिजली की तरह नहीं गिरता। वह सुबह की धुंध की तरह उतरता है—धीरे, बेहद धीरे।

और जब उतरता है, तब मन के संसार में एक दीया जलाता है—धैर्य का अनंत दीप।

प्रशासनिक तंत्र की तय हो जवाबदेही..

उत्तर भारत की सर्दियां गोवा के लिए वरदान होती हैं। अरब सागर तटीय इस राज्य में सर्दियों में उत्तर भारतीय सैलानियों की आवक बढ़ जाती है। लेकिन हो सकता है कि इस बार यह आवक कम हो। गोवा में साल के आखिरी दिनों और अगले साल की छुट्टियां मनाने का मन बना चुके सैलानियों में इस बार हिचक हो सकती है। वजह है, यहां के मशहूर नाइट क्लब 'बर्क बाय रोमियो लेन' में लगी आग, जिसमें पांच सैलानी समेत पच्चीस लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्घटनाएं कह कर नहीं आतीं, लेकिन उनकी रोकथाम की मुकम्मल तैयारी से शायद ही किसी को इनकार हो। लेकिन समंदर के किनारे से छनकर आती रोशनियों के बीच स्थित गोवा के इस नाइट क्लब में लगी आग और उसमें गई निर्दोष जान ने सबसे बड़ा सवाल उस प्रशासनिक तंत्र पर लगाया है, जिस पर इस हादसे की रोकथाम की जिम्मेदारी थी। बताया जा रहा है कि अनधिकृत ढंग से इस नाइट क्लब का निर्माण किया गया था। इस अनधिकृत निर्माण को तोड़ने के लिए गोवा की संबंधित पंचायत ने निर्देश भी दे रखा है। आग लगने की दशा में उसके रोकथाम और बचाव को लेकर इस नाइट क्लब में कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, यह क्लब बेहद संकरी जगह पर है, जहां आसानी से जाना संभव नहीं है।

भारत में एक चलन स्वीकार कर लिया गया है। नियमावलियां तो खूब बनाई गई हैं। लेकिन वे सिर्फ दस्तावेजों के लिए हैं। जिन्हें इन नियमावलियों को लागू करने की जिम्मेदारी है, जिन पर इन नियमावलियों को तोड़ने वालों को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित करने-कराने की जवाबदेही है, अक्सर वे इससे आंखें मूंद लेते हैं। कई बार नियम तोड़ने वालों से संबंध पलकों को मोड़ने का जरिया बनते हैं तो कई बार रिश्वत की रकम का बोझ पलकों को झुकने के लिए मजबूर कर देता है। भारत के प्रशासनिक तंत्र का बड़ा हिस्सा इसी तरह की मानसिकता में काम करता है। वह दुर्घटनाओं और हादसों का इंतजार करता है। वह तभी जागता है, जब हादसे हो जाते हैं, उनमें मासूम जानें चली जाती हैं। तब उन्हें नियमों की तेजी से याद आने लगती है। प्रशासनिक तंत्र की बंद आंखे तब ऐसे खुल जाती हैं, जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। तब उसे अनधिकृत निर्माण भी दिखने लगता है, तब उसे कारवाई की भी सूझने लगती है। कारवाई होती भी है। गोवा के 'बर्क बाय रोमियो लेन' क्लब के मालिकों पर भी होगी, लेकिन इसका असर कितनी देर तक रहेगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि वक्त बीतते-बीतते कारवाई में ढिलाई भी शुरू हो सकती है और अगर किसी सामाजिक संस्था, किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी न्यायिक व्यवस्था की निगाह उस पर नहीं पड़ी तो कारवाई धीरे-धीरे टलती चली जाएगी, उसकी तासीर ठंडी होती जाएगी और फिर हो सकता है कि नियमों को तोड़ने वाले किसी और जगह नियम तोड़कर ऐसा ही किसी और नाम से नाइट क्लब चलाने लगें

भारत में अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचा अपने राजकाज को चलाने के लिए बनाया था। उसे लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए बनाया था। देखते ही देखते यह तंत्र स्टील फ्रेम में तब्दील होता चला गया। वैसे भी जर्मन दार्शनिक मैक्स वेबर इसे स्टील फ्रेम ही बताते हैं। संविधान सभा ने भारत के भावी प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा को लेकर चर्चा की थी। उसने इस पर गंभीर विमर्श किया था। संविधान सभा में प्रशासनिक तंत्र पर व्यापक चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो स्वतंत्र भारत के लिए प्रभावी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह हो । संविधान सभा के सदस्यों को संदेह था कि भारत की भावी नौकरशाही भारतीय मूल्यों और भारतीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं हो पाएगी। इसी लिए संविधान सभा में तत्कालीन सदस्यों ने नौकरशाही की भूमिका पर ना सिर्फ व्यापक चर्चा की, बल्कि उसकी राजनीतिक तटस्थता, कार्यक्षमता, जवाबदेही और नए स्वतंत्र राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे में उसकी स्थिति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया । इन बहसों का उद्देश्य एक ऐसी सिविल सेवा प्रणाली स्थापित करना रहा, जो संविधान के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान हो और लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो। सवाल यह है कि क्या संविधान सभा की बहसों के अनुरूप आज की नौकरशाही बन पाई है। उसके ज्यादातर हिस्सों को देखिए तो लगता है कि बिल्कुल नहीं। आज भी उसमें अंग्रेजी राज जैसी अकड़ है, उसका ध्यान ज्यादातर अपनी ताकत को बचाए रखने और उसके जरिए आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने पर है। भारत का शायद ही कोई राज्य हो, जहां की नौकरशाही में अकूत संपत्ति के मालिक, भ्रष्टाचारी और कर्त्तव्यहीन अफसर ना होंगे। मध्य प्रदेश जैसे जिन राज्यों में लोकपाल व्यवस्था कायम है, वहां आए दिन ऐसे अफसरों पर छापे पड़ते हैं, उनके घर मिले नोटों को गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ती हैं। कई बार तो नोट गिनने में ही दो-दो तीन-तीन दिन लग जाते हैं। सवाल यह है कि क्या अफसरों के पास अकूत धन उनके सत्कर्मों और कर्त्तव्यपरायणता के चलते आता है? निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब ना में हैं। पैसे आते हैं, अवैध निर्माण को बढ़ावा देने से, नियमों की अवहेलना करने वालों से मिलने वाली रकम से, लोक के लिए आए फंड की बंदरबांट से। बिना प्रशासनिक मिलीभगत के यह कल्पना बेकार है कि किसी नाइट क्लब में अवैध निर्माण होगा, वह संकरी गलियों में चलेगा और उसमें सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी होंगे। हाल के दिनों में सड़कों पर बसों के आग का गोला बनने की घटनाएं भी बढ़ी हैं, अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर भी चले हैं या चल रहे हैं, सवाल यह है कि क्या खटारा बसें बिना प्रशासनिक मिलीभगत और लापरवाही से सड़कों पर चल सकती हैं, क्या अवैध निर्माण बिना प्रशासनिक सहयोग के हो सकता है, निश्चित तौर पर ऐसे सवालों का जवाब ना में है। जब भी हादसे होते हैं, जब कोई बस आग का गोला बनती है, जब अवैध निर्माण सामने आता है, संबंधित बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, अवैध निर्माण गिरा दिया जाता है। लेकिन इन सबके लिए प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वे साफ बच जाते हैं।

अभियान

जो समय के पर्वतों को चीरकर बहती है और अंततः मनुष्य के भीतर ज्ञान के सागर में विलीन हो जाती है

कहानी वहीं से नहीं शुरू होती जहाँ आँखें देखती हैं, बल्कि वहाँ से शुरू होती है जहाँ मन पहली बार थकान महसूस करता है।

बहुत समय पहले, एक शहर था जो अपने शोर, चमक और बुद्धिजीवियों की भीड़ के लिए प्रसिद्ध था। उसी शहर में एक युवा विद्वान रहता था—तेज़ दिमाग, तेज़ सवाल, तेज़ महत्वाकांक्षा। उसके कमरे की दीवारों पर किताबें थीं, कागज़ थे, सूत्र थे, और आधी रात तक जलता हुआ एक अकेला दीपक—जो उसके भीतर के अंधेरे को कम नहीं कर पा रहा था।

ज्ञान की भूख उसे अंदर से खाती थी, पर जितना पढ़ता—मन उतना ही उलझ जाता। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस व्यक्ति से मिलेगा जिसकी बुद्धि को लोग प्रकाश का दूसरा नाम कहते थे—वॉल्टेयर।

युवक ने दरवाज़ा खटखटाया।

अंदर से धीमी आवाज आई, "अंदर आओ।"

कमरे में पुस्तकों की खुशबू थी, और खिड़की से आती हल्की हवा में पुराने ज़माने की किसी गहन सोच की धड़कन मिल रही थी। वॉल्टेयर ने नजर उठाई, और युवक ने अपनी सारी बेचैनी एक ही सांस में उड़ेल दी—

"मैं दुनिया को समझना चाहता हूं, पर जितना समझता हूं, उतना ही खो जाता हूं। ज्ञान बढ़ता है, पर रोशनी कम होती जाती है। क्या यह रास्ता कहीं ले जाएगा भी?"

वॉल्टेयर ने उसे ध्यान से देखा—उस नजर में निर्णय नहीं, करुणा थी।

वह उठे और बोले, "चलो, तुम्हें एक चीज दिखाता हूं।"

दोनों एक शांत पगडंडी पर चलते हुए पिछवाड़े के बाग में पहुँचे। वहां न कोई फूलों की सजावट थी, न किसी तरह की दिखावट। बस मिट्टी थी, जीवन था, हवा की सरसराहट थी, और अनेक पौधे—कुछ लहराते, कुछ झुके हुए, कुछ सूखे और कुछ अभी अंकुरित होने की प्रतीक्षा में।

युवक ने चारों ओर नजर डाली, और धीमे से कहा,

"यह बाग अधूरा लगता है। कुछ पौधे तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे।"

वॉल्टेयर ने उसकी तरफ देखा और हल्की-सी मुस्कान के साथ कहा,

"पर क्या तुमने देखा कि यह बाग कभी शोर नहीं करता कि वह अधूरा है? यह स्वीकार करता है कि हर पौधे की अपनी गति है। कुछ तेज़ बढ़ते हैं, कुछ धीमे, कुछ परिस्थितियों से लड़ते-लड़ते थक जाते हैं पर बाग कभी शिकायत नहीं करता।"

वे मिट्टी को उंगलियों से स्पर्श करते हुए बोले—

"ज्ञान भी एक बाग है। तुम सब पौधों को एक साथ, एक ही दिन में खिलाना चाहते हो। पर ऐसा होता नहीं।"

युवक के भीतर टंकार-सी उठी,

"पर मुझे जानना है समझना है"

वॉल्टेयर ने सिर हिलाया।

"जानने की इच्छा अच्छी है। पर धैर्य की अनुपस्थिति ज्ञान को अंधेरा बना देती है। तुम ज्ञान को मजबूर कर रहे हो कि वह आज ही अपना फल दे दे।

पर ज्ञान का फल केवल समय देता है।"

उन्होंने एक सूखे पौधे की तरफ इशारा किया।

"देखो इसे। यह अभी कमजोर है, पर अगर मैं चाहूं कि यह अगले ही पल हरा हो जाए, और मैं इसे खींच दूं तो यह मर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा-थोड़ा पानी दूं, उसकी जड़ों को सांस लेने दूं, उसकी गति को स्वीकार करूं तो यह एक दिन मजबूत होगा।"

युवक की सांस भारी हो उठी।

"तो क्या मेरी उलझन गलत है?"

वॉल्टेयर ने गहरी आवाज़ में कहा—

"उलझन गलत नहीं होती। उलझन मन का यह स्वीकार करना है कि वह नई दिशा की तलाश में है। गलत केवल अधीरता होती है। तुम दुनिया को एक ही बार में समझना चाहते हो। यह वैसा है जैसे कोई नदी से कहना चाहे कि वह एक ही लहर में समुद्र तक पहुंच जाए।"

युवक के भीतर जैसे कोई गांठ पिघलने लगी।

बाग में धीमी हवा चली, पत्ते हिले, और प्रकृति का अपना संगीत गूँज उठा।

वॉल्टेयर ने कहा—

"मन भी एक नदी की तरह है। जितना उसे बहने दोगे, उतना ही वह साफ़ होता जाएगा। और नदी छोटी-छोटी धाराओं से बनती है—धैर्य की धाराओं से, अनुभव की बूंदों से, समय की गति से।"

युवक की आँखों में पहली बार शांति की परत उतर गई।

वह बोला,

"तो मुझे क्या करना चाहिए?"

वॉल्टेयर ने जैसे उसके भीतर का प्रश्न बहुत पहले से सुन लिया था।

उन्होंने कहा—

"जो तुम्हारे हाथ में है—उसे करो। जो नहीं है—उसे जाने दो।

ज्ञान को बहाव दो, भार मत बनाओ।

दुनिया को समझने की कोशिश मत करो—दुनिया को महसूस करो।

आप अपने भीतर रोशनी भरोगे, तब दुनिया अपने आप समझ में आएगी।"

वापसी के रास्ते युवक के कदम बदल गए थे।

जब आया था—वह भीतर से टूटा हुआ था।

जब लौट रहा था—उसके भीतर एक धीमी, शांत, गहरी नदी बहने लगी थी।

उसने महसूस किया कि

ज्ञान की ऊँचाई नहीं, अनुभव की शांति मन को मुक्त करती है।

और उस शांति तक पहुँचने का पुल—धैर्य है। इस तरह वॉल्टेयर का यह छोटा-सा बाग, एक युवक के भीतर पूरी उम्र के लिए एक शांत नदी बन गया—जो कभी सूखती नहीं, केवल बहती रहती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का अभिनव दृष्टिकोण

- कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की रीजनल कॉन्फ्रेंस 10 से 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में आयोजित होगी
- वीजीआरसी के प्रमोशन के लिए दिल्ली में संवाद-वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित
- रशिया, कनाडा और सिंगापुर सहित 20 से अधिक देशों के मिशन और दूतावास के प्रतिनिधी सहभागी हुए
- फिशरीज, पोर्ट, धोलेरा एसआईआर और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर अर्थपूर्ण संवाद का प्लेटफॉर्म

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से गुजरात वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बना है। इतना ही नहीं, गुजरात ने दुनिया भर के उद्योगों-निवेशकों के लिए 'गेट-वे टू द फ्यूचर' की विशेष पहचान स्थापित की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मिली इस सफलता के बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य विशेषताओं, क्षमताओं और आर्थिक विकास की संभावनाओं को उजागर करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के आयोजन का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शक इस वीजीआरसी के राज्य में चार संस्करण आयोजित करने की योजना के अंतर्गत आगामी 10 से 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र की वीजीआरसी का आयोजन किया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस संदर्भ में शुक्रवार, 12 दिसंबर को नई दिल्ली में एक चर्चा-संवाद सत्र का आयोजन किया। इस चर्चा-संवाद

सत्र में, वीजीआरसी में देश और दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनके समक्ष वीजीआरसी की विशेषताओं की प्रस्तुति के साथ ही विकास संभावनाओं वाले सेक्टरों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

इस संवाद सत्र में 'क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं' थीम के अनुरूप और समावेशी, नवोन्मेषी एवं सतत-टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए गुजरात की विशेषताएं प्रस्तुत की गईं।

विशेषकर, फिशरीज, पोर्ट्स, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर सार्थक संवाद और बीटूबी (बिजनेस-टू-बिजनेस) की संभावनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा-परामर्श हुआ। साथ ही, वीजीआरसी में साझेदार देश बनने के फायदे, नेटवर्किंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे विषयों पर भी वार्तालाप किया गया।

उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने चर्चा सत्र में मेहसाणा में आयोजित उत्तर गुजरात क्षेत्र की पहली वीजीआरसी को मिली सफलता और 3.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की जानकारी दी।

इस संवाद में रशिया, इजरायल, सिंगापुर, यूएई, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा, श्रीलंका, ओमान, आइसलैंड, गुयाना, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, कतर, तंजानिया, युगांडा और उज्बेकिस्तान सहित 20 से अधिक देशों के विदेशी मिशन और दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव, केंद्रीय मत्स्य पालन संयुक्त सचिव और इन्वेस्ट इंडिया की राज्य सुविधा टीम तथा गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, आर्थिक मामलों की सचिव श्रीमती आरती कंवर, सचिव श्री संदीप कुमार, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप, पर्यटन सचिव डॉ. राजेन्द्र कुमार, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ श्री राजकुमार बेनीवाल, रेजिडेंट कमिश्नर सह मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और धोलेरा एसआईआर के सीईओ श्री कुलदीप आर्य मौजूद रहे।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर के बीच,चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अजमेर में उर्स फेस्टिवल के लिए यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को समायोजित करने के लिए बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09027/09028 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल [04 फेरे]

ट्रेन संख्या 09027 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर स्पेशल सोमवार और गुरुवार, 22 एवं 25 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 12:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:20 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09028 अजमेर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल मंगलवार और शुक्रवार, 23 एवं 26 दिसंबर, 2025 को अजमेर से 10:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, दहानू रोड, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर और नसीराबाद स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09027 की बुकिंग 14 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच क्रिसमस स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा क्रिसमस और नववर्ष के दौरान यात्रियों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 04061/4062 साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती स्पेशल (8 फेरे)

ट्रेन संख्या 04061 साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल 22, 25, 28 और 31 दिसंबर 2025 को साबरमती से प्रातः 05.15 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन रात्री 23.30 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। इसी तरह से ट्रेन संख्या 04062 दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती स्पेशल 21, 24, 27 और 30 दिसंबर 2025 को दिल्ली सराय रोहिल्ला से 08.10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 00.30 बजे

साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं., ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुडगाँव एवं दिल्ली कैंट स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन एसी I-टियर एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन संख्या 04061 की बुकिंग 14 दिसंबर 2025 सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सोना-चांदी के वायदा में तेजी जारीः दोनों कीमती धातुओं के वायदाओं में ऑल टाइम हाई भाव दर्ज हुए

क्रूड ऑयल वायदा में 36 रुपये की वृद्धिः कमोडिटी वायदाओं में 54159.48 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 204265.12 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 45147.02 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 32936 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 258438.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 54159.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 204265.12 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 32936 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3278.41 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 45147.02 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132442 रुपये के भाव पर खूलकर, 134966 रुपये के ऑल टाइम हाई और 132275 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132469 रुपये के पिछले बंद के सामने 2432 रुपये या 1.84 फीसदी की मजबूती के साथ 134901 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 2021 रुपये या 1.91 फीसदी बढ़कर 107727 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 245 रुपये या 1.85 फीसदी बढ़कर 13484 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा 130905 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 133072 रुपये और नीचे में 130552 रुपये पर पहुंचकर, 2115 रुपये या 1.62 फीसदी बढ़कर 133020 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम 131334 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 133388 रुपये और नीचे में 130901 रुपये पर पहुंचकर, 131137 रुपये के पिछले बंद के सामने 2163 रुपये या 1.65 फीसदी बढ़कर 133300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 196958 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 201388 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 196957 रुपये पर पहुंचकर, 198942 रुपये के पिछले बंद के सामने 1589 रुपये या 0.8 फीसदी बढ़कर 200531 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1783 रुपये या 0.9 फीसदी की तेजी के संग 200993 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1785 रुपये या 0.9 फीसदी की मजबूती के साथ 201008 रुपये प्रति किलो बोला गया। मेटल वर्ग में 5113.39 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 7.55 रुपये या 0.68 फीसदी बढ़कर 1119.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 2.2 रुपये या 0.69 फीसदी की तेजी के संग 322.3 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 10 पैसे या 0.04 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 280.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 25 पैसे या 0.14 फीसदी बढ़कर 182.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3745.73 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5230 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5260 रुपये और नीचे में 5200 रुपये पर पहुंचकर, 36 रुपये या 0.7 फीसदी बढ़कर 5215 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 36 रुपये या 0.69 फीसदी की तेजी के संग 5216 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 380.9 रुपये के भाव पर खूलकर, 386.2 रुपये के दिन के उच्च और 370.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 381.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.4 रुपये या 1.15 फीसदी की बढ़त के साथ 385.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 4.1 रुपये या 1.08 फीसदी बढ़कर 385.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 909.5 रुपये पर खूलकर, 3.1 रुपये या 0.33 फीसदी गिरकर 925.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 24432.28 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 20714.74 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4332.68 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 248.12 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 19.38 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 513.22 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 903.18 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2829.68 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 15256 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 71979 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 18847 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 298492 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 32784 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17400 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 41713 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 118375 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 18628 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 40170 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 32632 पॉइंट पर खूलकर, 32975 के उच्च और 32400 के नीचले स्तर को छूकर, 373 पॉइंट बढ़कर 32936 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 70 पैसे के सुधार के साथ 32 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 380 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.45 रुपये की बढ़त के साथ 21.7 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 136000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 874 रुपये की बढ़त के साथ 2058.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 198000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1077 रुपये की बढ़त के साथ 7908 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.46 रुपये की बढ़त के साथ 19.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.48 रुपये की बढ़त के साथ 10.84 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 22.1 रुपये की गिरावट के साथ 61.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 380 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5 पैसे की नरमी के साथ 17 रुपये हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में गुजरात मीडिया क्लब द्वारा आयोजित 'भारतकूल अध्याय-2' कार्यक्रम का प्रारंभ कराया

हर आलोचना के पीछे का भाव सकारात्मक तथा लोक कल्याण का होना चाहिए : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-
- नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलकर विकसित भारत का सपना साकार करेंगे
- विकसित भारत @2047 के संकल्प में गुजरात लीड लेगा
- सनातन मूल्यों के संरक्षण के साथ युवा शक्ति समय के साथ कदम मिलाए

गुजरात के विकास में 'भाव, राग एवं ताल' महत्वपूर्ण : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में आयोजित 'भारतकूल अध्याय-2' के शुभारंभ अवसर पर मीडिया के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के विकास में मीडिया की भूमिका सहायक की है। सरकार हमेशा नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे में नीतियों में सुधार और लोक कल्याण के लिए उचित आलोचना आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे का भाव सकारात्मक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में वर्ष-2025 भारत के गौरव को उजागर करने वाला वर्ष बन रहा है। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती, सरदार साहब की 150 वीं जयंती तथा हमारे राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एकता नगर में गत महीने आयोजित 'राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस' तथा भव्य 'भारत पर्व' जैसे कार्यक्रमों में अनेकता में एकता का भाव दर्शाती सांस्कृतिक झलक लोगों को देखने को मिली तथा भारतीय परंपरा पुनर्जीवित हुई।

मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति का महत्व समझाते हुए कहा कि विश्व में भारत की पहचान उसकी प्राचीन तथा परम सत्य तक ले जाने वाली संस्कृति के कारण ही है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने पश्चिम के लोगों को भारतीय संस्कृति की केवल एक छोटी-सी झलक ही दिखाई थी, जिससे वे अभिभूत हो गए थे। जो

लोग इसमें गहराई से उतरे, उन्होंने अपना जीवन इस संस्कृति को समर्पित कर दिया। इसलिए यह भी अत्यंत आवश्यक है कि नई पीढ़ी को हमारी सनातन सभ्यता के मूल मूल्यों से अवगत कराया जाए।

श्री पटेल ने 'भारतकूल' के इस दूसरे अध्याय के आयोजन के लिए गुजरात मीडिया क्लब और गुजरात यूनिवर्सिटी को बधाई देते हुए, युवा शक्ति को उनके सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को एक उपयुक्त मंच बताया।

उन्होंने बलपूर्वक कहा कि देश को आगे ले जाने और प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो 'विकसित भारत @2047' का सपना अवश्य साकार होगा और उसमें गुजरात अग्रसर होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति से समय के साथ कदम मिलाते हुए स्वदेशी, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण तथा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे संकल्पों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने का अनुरोध किया।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुजरात के विकास में 'भाव, राग एवं ताल' को महत्वपूर्ण बताते हुए 'भारतकूल' के कार्यक्रमों में 'भाव, राग और ताल' जैसे अद्भुत विषयों का चुनाव करने के लिए आयोजकों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात के विकास की छलांग की शुरुआत की, उसके पीछे राज्य के विकास का भाव मुख्य था। प्रधानमंत्री के मतानुसार अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा हो तो खुशी होनी चाहिए और कुछ बुरा हो तो दुख होना चाहिए; यही भावना विकास के लिए अनिवार्य है। उप मुख्यमंत्री ने भाव, राग और ताल; इन तीनों विषयों पर युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में, सरकार में संस्कृति, विरासत, राग और ताल के क्षेत्र में किए गए अद्भुत कार्यों को उल्लेखनीय बताया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वडनगर में देश का सबसे बड़ा म्यूजिक स्टूडियो बनने जा रहा है और वडोदरा में भी इसी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

श्री संघवी ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में संस्कृति संवर्धन सहित क्षेत्रों में जितना काम हुआ है, वह नरेन्द्र मोदी के शासन की शुरुआत से आज तक निरंतर जारी है। उन्होंने रिसर्च डॉक्यूमेंट और चर्चा से निकले सुझावों को सरकार को सौंपने का अनुरोध किया, ताकि ये विषय मात्र कार्यक्रमों तक सीमित न रहें और उन्हें सरकार के कार्यों में जोड़ा जा सके।

अहमदाबाद मंडल की टाइम टेबल पार्सल सेवा: छोटे व्यवसायों के लिए तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सेवा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा टाइम टेबल पार्सल सेवा (ट्रेन संख्या 00907) का संचालन 21 सितंबर 2025 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यह साप्ताहिक टाइम-टेबल्ड पार्सल ट्रेन प्रत्येक रविवार को कांकरिया (अहमदाबाद) से प्रस्थान कर संकरैल (कोलकाता) तक 2074 किमी की दूरी मात्र 54 घंटे 45 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन का मार्ग में आणंद, उधना, टाटानगर और खड़गपुर जैसे प्रमुख व्यावसायिक स्टेशनों पर निर्धारित ठहराव उपलब्ध हैं, जिससे देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच तेज़ और विश्वसनीय माल ढुलाई सुनिश्चित होती है। इस ट्रेन में 20 पार्सल वेन (VP) है जिसकी प्रति वेन क्षमता 23 टन है। सिंगल वेन (23 टन) की बुकिंग भी की जा सकती है। इस टाइम टेबल पार्सल सेवा की शुरुआत के बाद से अहमदाबाद मंडल लगातार लोडिंग में प्रमुख योगदान दे रहा है। 20 पार्सल वेन के रेक में औसतन 60–70% पार्सल स्पेस का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। नवंबर 2025 में टाइम टेबल पार्सल सेवा की कुल पाँच ट्रिप संचालित हुईं, जिनसे 0.79 करोड़ का पार्सल राजस्व प्राप्त हुआ। छोटे और मध्यम व्यवसायों की बढ़ती लॉजिस्टिक मांग को ध्यान में रखते हुए यह शुरू की गई है।

इस सेवा ने अब तक 12 सफल यात्राएँ पूरी की हैं, जिनमें 1,78,153 पैकेजों

कुशल हेंडलिंग किया गया तथा लगभग 3000 टन माल का परिवहन कर कुल 1.66 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। लगातार 60% से अधिक लोडिंग उपलब्ध कराना इस बात का प्रमाण है कि यह सेवा बाज़ार की ज़रूरतों को पूर्ण रूप से पूरा कर रही है।

यह तेज़, किफायती और समयबद्ध सेवा छोटे व्यवसायों को निम्न प्रमुख लाभ प्रदान कर रही है —

- **तेज़ डिलीवरीः** टाइम-टेबल्ड सेवा होने के कारण उत्पाद पूर्वी भारत के बाज़ारों तक निश्चित समय पर पहुँच रहे हैं।
- **कम लागत में माल ढुलाईः** सड़क परिवहन की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती विकल्प उपलब्ध हो रहा है।
- **व्यापक बाज़ार पहुँचः** आणंद, उधना, टाटानगर और खड़गपुर जैसे प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों से सीधा संपर्क छोटे व्यापारियों को नए ग्राहक और नए बाज़ार उपलब्ध करा रहा है।
- **त्वरित समाधान और सुगम प्रक्रियाः** अहमदाबाद मंडल द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए आसान बुकिंग, तेज़ प्रतिक्रिया और सुव्यवस्थित पार्सल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है।

अहमदाबाद मंडल की यह पहल छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स विक्रेताओं और स्थानीय उद्योगों के लिए एक प्रभावी, तेज़ और भरोसेमंद परिवहन सुविधा के रूप में उभर रही है। मंडल आगे भी समय-संवेदी लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देते हुए व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे का बोरीवली और गोरेगांव स्टेशनों,के बीच रविवार, 14 दिसम्बर, 2025 को जम्बो ब्लॉक

रेल पथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा बोरीवली और गोरेगांव स्टेशनों के बीच रविवार, 14 दिसम्बर, 2025 को 10.00 बजे से 15.00 बजे तक अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर पांच घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान गोरेगांव और बोरीवली के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइन की सभी ट्रेनें फास्ट लाइनों पर चलाई जाएंगी। ब्लॉक के कारण कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी तथा अंधेरी और बोरीवली की कुछ ट्रेनें गोरेगांव स्टेशन तक हार्बर लाइन पर चलाई जाएंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, 2, 3 और 4 से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी।

फियो ने प्रधानमंत्री के जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के तीन देशों के दौरे का स्वागत किया; इसे व्यापार और आर्थिक साझीदारी को गहरा करने का एक बड़ा अवसर बताया

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2025ः फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 15-18 दिसंबर, 2025 तक होने वाले तीन देशों के दौरे की घोषणा का दिल से स्वागत करता है। यह दौरा भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अहम समय पर हो रहा है और पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत की आर्थिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बड़ा अवसर प्रदान करता है।

इस घटनाक्रम पर चर्चा करते हुए, फियो के अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में विशेष साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के भारत की प्रतिबद्धता का एक मजबूत संकेत देता है। ऐसे समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव हो रहे हैं, इन साझेदारी को गहरा करने से भारतीय निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंचने, व्यापार मार्गों में विविधता लाने और लंबे समय के व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलेगी।"

महामहिम किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन के आमंत्रण पर 15-16 दिसंबर, 2025 को प्रधानमंत्री का जॉर्डन दौरा राजनयिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ के साथ हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और बढ़ते रिश्तों को दिखाता है। उम्मीद है कि बातचीत में

द्वीपक्षीय सहयोग के पूरे कार्यक्षेत्र के साथ-साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी बात होगी। श्री रल्हन ने कहा कि जॉर्डन वेस्ट एशिया और बड़े मिडिल ईस्ट रीजन के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे है। अप्रैल-अगस्त, 2025-26 के दौरान जॉर्डन के साथ भारत का कुल द्वीपक्षीय व्यापार 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सिर्फ़ पांच महीनों में लगभग 461 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। और इसलिए, जॉर्डन के साथ बेहतर आर्थिक बातचीत से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, आईटी सर्विसेज़ और फ़ूड और एग्री-प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टरों में भारतीय निर्यातकों के लिए मौके और बढ़ेंगे, जिससे 2030 तक निर्यात बढ़कर 5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है।

16-17 दिसंबर, 2025 को अपने दौरे के दूसरे हिस्से में, प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. अबी अहमद अली के बुलावे पर इथियोपिया जाएंगे। यह दौरा प्रधानमंत्री का इथियोपिया का पहला दौरा है, जो तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अफ्रीका में भारत के सबसे ज़रूरी साझीदारों में से एक है। फियो प्रमुख ने कहा कि इथियोपिया अफ्रीकी क्षेत्र का एक अहम सदस्य है और भारत के साउथ-साउथ कोऑपरेशन में एक ज़रूरी साझीदार है। यह दौरा व्यापार, निवेश और विकास साझीदारी को गहरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय निर्यातक, खासकर ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और एजुकेशन सर्विसेज़ में, इथियोपिया के बढ़ते मार्केट में बहुत ज़्यादा संभावना देखते हैं, जहां दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय व्यापार 550 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

प्रधानमंत्री अपने दौरे के आखिरी हिस्से में, महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक के आमंत्रण पर, दूसरी बार 17-18 दिसंबर, 2025 को ओमान जाएँगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ है। चूंकि भारत और ओमान एक लंबे समय से चली आ रही और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसे मज़बूत व्यापार संबंधों,ऊर्जा सहयोग और कल्चरल लिंकेज का सपोर्ट है। श्री रल्हन ने ज़ोर देकर कहा कि ओमान हमेशा से गल्फ में भारत के सबसे भरोसेमंद आर्थिक साझेदारों में से एक रहा है। यह दौरा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, फ़ूड सिक्योरिटी और एमएसएमई सहयोग में नए रास्ते तलाशने का एक शानदार अवसर देता है। ओमान के साथ द्वीपक्षीय संरचना को मज़बूत करने से भारत के निर्यात सेक्टर पर सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा, जो 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निर्यात है। हालांकि, चूंकि हम एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के आखिरी चरण में हैं। ओमान के साथ हुए इस समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को दोगुना करने में बहुत ज़रूरी बढ़ावा मिलेगा।

फियो का मानना है कि प्रधानमंत्री का तीन देशों का दौरा भारत की व्यापार कूटनीति को काफ़ी मज़बूत करेगा और बहुत ज़्यादा रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। श्री रल्हन ने भरोसा जताया कि फियो इस ज़रूरी दौरे के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है और इन राजनयिक बातचीत को भारतीय निर्यातक समुदाय के लिए ठोस व्यापार और निवेश के मौकों में बदलने के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा और उनके साथ जुड़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न शिक्षा योजनाओं के तहत 13 लाख से अधिक छात्रों को 370 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सहायता वितरित की

- उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की प्रेरक उपस्थिति
- नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए सहायता वितरित
- बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा हो रहा है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- राज्य सरकार ने अनेक शैक्षणिक योजनाएं कार्यरत कीं, ताकि छात्रों पर आर्थिक बोझ न पड़े : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी
- शिक्षा में किया गया निवेश केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि विकसित गुजरात के निर्माण की मजबूत नींव है : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा

(जीएनएस)। गांधीनगरः मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की उपस्थिति में नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के 13 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों को 370 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले ढाई दशक में राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री का बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने का लक्ष्य साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी सफलतापूर्वक पूर्ण करें तथा कन्या शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन मिले, इसकी चिंता करते हुए नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजनाएं शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'बेटी बचाओ' अभियान के जरिए देश में बेटियों की शिक्षा को काफी बड़ी गति दी है। श्री पटेल ने कहा कि जब उन्होंने 2001 में गुजरात का सेवादायित्व संभाला, तब अनेक समस्याएं थीं। श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे समय में देश में एक उदाहरण पेश किया कि, किस प्रकार एक राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं गांव-गांव जाकर बेटियों की शिक्षा का सेवा-यज्ञ शुरू करता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री उन्हें मिलने वाले उपहारों की नीलामी करके उससे प्राप्त होने वाली राशि को कन्या केळवणी (शिक्षा) के लिए देने की एक नई परंपरा शुरू की। इन सभी के परिणामस्वरूप लोगों में भी बेटियों को स्कूल भेजने की जागरूकता बढ़ी और शाला प्रवेशोत्सव-कन्या केळवणी महोत्सव की सफलता के चलते बेटियों के ड्रॉपआउट की दर 37 फीसदी से घटकर 2 फीसदी से भी नीचे आ गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब गांवों में विज्ञान संकाय के स्कूलों की संख्या बहुत ही कम थी जबकि आज विज्ञान संकाय के स्कूलों की संख्या 2834 हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2001 में केवल 775 कॉलेज थे, आज गुजरात में 3200 से अधिक कॉलेज छात्रों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 12 में विज्ञान संकाय के बाद इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए जाना हो, तो केवल 139 कॉलेज थे, आज इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 288 पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवादायित्व संभाला तब 1175 मेडिकल सीटें थीं, जो आज बढ़कर 7000 से अधिक हो गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल में पढ़ाई करने वाली बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि योजना से अब तक राज्य की 24 हजार से अधिक बेटियों को सहायता प्रदान की गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात और देश का भविष्य जिनके हाथों में हैं, ऐसे आज के छात्रों के लिए गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप योजनाओं में से चार योजनाओं के अंतर्गत आज 13 लाख से अधिक छात्रों के बैंक खातों में सीधे 370 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति सहायता डीबीटी के जरिए भेजी गई है। अब तक, राज्य सरकार ने इन चारों योजनाओं के अंतर्गत कुल 13.50 लाख से अधिक छात्रों को 1332 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है।

श्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को उनके दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं और अपने स्वभाव के अनुसार सौम्यता के साथ पूरे मंत्रिमंडल की टीम को भी इसी प्रकार जनहित के निर्णय लेने के लिए लगातार प्रेरणा, छूट और हिम्मत दी है। शिक्षा विभाग की जिन चार योजनाओं के तहत आज छात्रवृत्ति सहायता दी गई है, उनमें से एक फ्लैगशिप योजना भी उनके ही निर्णय का हिस्सा है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस प्रकार के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिखाया है कि शिक्षा विभाग और हमारे भविष्य इन छात्रों के लिए उनका कितना समर्पण और योगदान है।

श्री संघवी ने नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के बारे में कहा कि गुजरात में जिस तरह से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऐसे में यह जरूरी है कि हमारे छात्र भी उसमें अपना योगदान दे सकें। यदि कोई माता-पिता अपने बच्चे को विज्ञान संकाय में पढ़ाना चाहते हों, तो उन पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इन नेक विचारों के साथ राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका राज्य के अनेक छात्र लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने छात्रवृत्ति वितरण के अवसर पर कहा कि गुजरात सरकार विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में शिक्षित और सक्षम समाज का निर्माण करने के लिए अडिग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग देश का भविष्य यानी आज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए योग्य दिशा देने को संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा में किया गया यह निवेश केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आने वाले समय के विकसित गुजरात के निर्माण की मजबूत नींव है। ये महत्वपूर्ण कदम गुजरात के छात्रों के जीवन को एक नई दिशा, नए अवसर और नए सपने देंगे।

गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली चार महत्वपूर्ण योजनाओं से आ रहे बदलावों की चर्चा करते हुए श्री वाजा ने कहा कि इन योजनाओं से लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो रहा है। नमो लक्ष्मी योजना बेटियों के सशक्तिकरण का शक्तिशाली माध्यम बनी है। इस योजना के तहत अब तक 10.49 लाख बेटियों को डीबीटी के जरिए 1033 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इसके चलते बेटियों की उपस्थिति में 73 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में 13.59 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के माध्यम से विज्ञान संकाय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए 1.5 लाख छात्रों को 151.84 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे विज्ञान संकाय के नामांकन में 6.34 फीसदी की वृद्धि हुई है। मेरिट और गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने वाली अन्य दो योजनाएं- मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 50,000 छात्रों को 86.14 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत 60,000 छात्रों को 61.27 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि ये चारों योजनाएं गुजरात के लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए ज्ञानसेतु का निर्माण कर रही हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव और प्रत्येक बालक को सशक्त बनाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस विचार को साकार करने वाले आज के कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा 13 लाख से अधिक छात्रों को डीबीटी के जरिए 370 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाने का यह एक ऐतिहासिक अवसर है।

श्रीमती जाडेजा ने आगे कहा कि हमारे देश का प्रत्येक बालक उज्ज्वल भारत का स्वप्न है, इसलिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती सहित अनेक योजनाओं के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर लगातार कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही आधारभूत सुविधाओं में लगातार वृद्धि करना, कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉपआउट अनुपात को कम करना और बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ राज्य के छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर सुंदर भविष्य बनाने का प्रयास करना है।

कार्यक्रम में गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर शहर संगठन प्रमुख डॉ. आशीष दवे, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री मुकेश कुमार, निदेशक, स्कूल कार्यालय श्री प्रजेश राणा, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

वीसीई को राज्य सरकार के विभागों द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में संवेदनशील निर्णय

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कमीशन के आधार पर ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई) के तौर पर काम करने वाले युवाओं की अधिकतम आय सुनिश्चित करने वाला संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने इस संदर्भ में यह निर्णय किया है कि वीसीई को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गए कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के जरिए शहरी क्षेत्र में उपलब्ध ई-सेवाओं जैसी ही सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराने के उद्देश्य से 'ई-ग्राम विश्वग्राम योजना' लागू की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई), ग्राम स्तर पर लोगों को 7/12, 8-अ और अधिकार पत्र की प्रतिलिपि, किसान रजिस्ट्रेशन, विभिन्न खेत उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड में संशोधन करने के लिए फॉर्म भरने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से वीसीई को विभिन्न योजनाओं की डेटा एंट्री से संबंधित कार्य भी सौंपा जाता है। इसके लिए संबंधित विभाग प्रत्येक कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट कमीशन के रूप में देय राशि निर्धारित करता है।

इसके कारण, अलग-अलग कामकाज और अलग-अलग विभागों द्वारा निर्धारित की जाने वाली मेहनताने की राशि अलग-अलग आधार पर तय होने से मेहनताने में समानता नहीं रह पाती।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के ध्यान में जब यह विषय आया, तब उन्होंने हाल ही में ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गांधीनगर में आयोजित 12वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीसीई के मेहनताने में समानता के लिए तत्काल निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के इन दिशा-निर्देशों के चलते पंचायत विभाग ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के विभागों को सूचित किया है कि अब किसी भी कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का मेहनताना देना होगा।

इतना ही नहीं, संबंधित विभागों को वीसीई को कामकाज सौंपने से पहले पंचायत विभाग तथा ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी को जानकारी भी देनी होगी।

महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने वडोदरा गोधरा–आणंद रेल खंड का किया संरक्षा निरीक्षण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 12 दिसम्बर 2025 को वडोदरा मंडल के वडोदरा – गोधरा – आणंद रेल खंड एवं प्रतापनगर कारखाने का वार्षिक संरक्षा निरीक्षण किया। अपने संरक्षा निरीक्षण में उन्होंने वडोदरा – गोधरा – आणंद रेलखंड में संरक्षा एवं सुरक्षा मानकों, ढांचागत विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, कर्मचारियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्य प्रगति कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया। आणंद स्टेशन पर महाप्रबंधक ने आणंद के माननीय विधायक श्री योगेश पटेल ज़ी एवं डाकोर स्टेशन पर थासरा के माननीय विधायक श्री योगेंद्र सिंह परमार ज़ी से मुलाकात की एवं उन्हें मंडल के विकास कार्यों एवं यात्री सुविधाओं की जानकारी दी। महाप्रबंधक के साथ विभिन्न विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्ष, वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके , अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

अपने वार्षिक संरक्षा निरीक्षण के दौरान श्री गुप्ता ने रोड अंडर ब्रिज, महत्त्वपूर्ण बड़े एवं छोटे पुलों, सेक्शनल स्पीड ट्रायल, पॉइंट एवं क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग सहित विभिन्न संरक्षा तत्वों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने वडोदरा, गोधरा, डेरोल एवं डाकोर स्टेशनों पर यात्री प्रतीक्षालय, टिकट बुकिंग सुविधा, शुद्ध पेय जल, पैदल ऊपरी पुल आदि उपलब्ध यात्री सुविधाओं का भी विस्तृत जायजा लिया।

छायापुरी यार्ड में महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने पॉइंट एवं क्रासिंग तथा इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्यूनिकेशन गैंग का निरीक्षण किया और रेल कर्मियों से संरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने छायापुरी – डेरोल खंड के बीच स्पीड ट्रायल का निरीक्षण भी किया।

गोधरा में श्री गुप्ता ने रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे कॉलोनी, गार्ड एवं ड्राइवरों के रनिंग रूम, RPF बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने गोधरा में रेलवे कम्युनिटी हाल का उद्‌घाटन भी किया।गोधरा - आणंद खंड पर उन्होंने महत्त्वपूर्ण बड़े एवं छोटे पुलों तथा कर्व के साथ - साथ डेरोल - खरसलिया एवं उमरेठ - आणंद खंड पर लेवल क्रासिंग गेट का निरीक्षण किया। श्री गुप्ता ने अपने दौरे के दौरान डेरोल एवं गोधरा में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया एवं मंडल के उपलब्धिओं एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वडोदरा मंडल द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। डेरोल, गोधरा और डाकोर में श्री गुप्ता ने रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया और रेलकर्मियों को गोधरा एवं डाकोर रेलवे कॉलोनी में उनके नए आवास की चाबी का वितरण भी किया।

महाप्रबंधक ने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को ट्रैक, समपार फाटकों तथा अन्य संरक्षा मानकों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए, ताकि ट्रेन सेवाएँ अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुसार संचालित की जा सकें।

रेल सुरक्षा रिकॉर्ड सुधार में वृद्धि : वार्षिक दुर्घटनाएं 2004-14 के औसत 171 से घटकर 2025-26 में अब तक 11 रह गई हैं

- सुरक्षा बजट लगभग तीन गुना बढ़कर 2013-14 के 39,463 करोड़ रूपए से चालू वित्त वर्ष में 1,16,470 करोड़ रूपए हो गया है
- अश्विनी वैष्णव ने कहा- कोहरे से बचाव के उपकरणों की संख्या 288 गुना बढ़ी है — 2014 के 90 से बढ़कर 2025 में 25,939 हो गई है
- पिछले चार महीनों में 21-21 स्टेशनों पर केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ट्रैक-सर्किट का काम पूरा हो गया है

(जीएनएस)। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी असामान्य घटना की रेलवे प्रशासन द्वारा गहन जांच की जाती है। तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य कारण की आशंका होने पर राज्य पुलिस की सहायता ली जाती है।

कुछ मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से भी मार्गदर्शन लिया जाता है। हालांकि, जांच का प्राथमिक माध्यम राज्य पुलिस ही है। यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों की जांच, कानून व्यवस्था बनाए रखना और पटरियों, पुलों, सुरंगों आदि रेलवे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

वर्ष 2023 और 2024 में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़/तोड़फोड़ की सभी घटनाओं में, राज्यों की पुलिस/जीआरपी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मामले दर्ज किए गए। इसके बाद जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी की गई और उन पर मुकदमा चलाया गया।

रेलवे द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी के साथ बेहतर समन्वय, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समन्वित कार्रवाई और निगरानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों और असुरक्षित इलाकों में रेलकर्मियों, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से लगातार गश्त की जा रही है।
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, असुरक्षित इलाकों में गश्त करने और खतरों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने हेतु विशेष दल गठित किए गए हैं।
- रेलवे पटरियों के पास पड़ी सामग्री को हटाने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका उपयोग शरारती तत्व रेलवे ट्रैक पर रखकर अवरोध उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं।
- रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों को ट्रैक पर अवांछित सामग्री रखने, रेल घटकों को हटाने के बाद होने वाली संभावित घटनाओं के परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उनसे सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का अनुरोध किया जा रहा है।
- रेलवे राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इनका गठन प्रत्येक राज्य में सम्बंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और खुफिया इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अपराध पर नियंत्रण, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और रेलवे परिसर के साथ-साथ चलती ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाता है। इसमें तोड़फोड़ की घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है और खुफिया जानकारी साझा की जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, स्थिति के अनुसार एनआईए और सीबीआई जैसी विशेष एजेंसियां भी शामिल हैं।
- केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों के अलावा, आरपीएफ की खुफिया इकाइयां, यानी सीआईबी और एसआईबी को नियमित रूप से जागरूक किया जाता है और उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वे खुफिया जानकारी एकत्र करें और पुलिस अधिकारियों के समन्वय से तोड़फोड़ के प्रयासों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

ट्रेन संचालन में सुरक्षा सुधारने के लिए भारतीय रेल द्वारा कई उपाय किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए अनुसार, परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2024-25 में 31 हो गई है।

गौरतलब है कि 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 1711 थी (औसतन 171 प्रति वर्ष), जो 2024-25 में घटकर 31 और 2025-26 में (नवंबर 2025 तक) और भी घटकर 11 रह गई।

पिछले पांच वर्षों के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई हैः-

रेल संचालन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाए गए विभिन्न सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैः-

1.भारतीय रेल में सुरक्षा सम्बंधी गतिविधियों पर व्यय में पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित रूप से वृद्धि हुई हैः-

सुरक्षा सम्बंधी गतिविधियों पर व्यय/बजट (रुपये करोड़ में)

2013-14	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
39,463	87,327	1,01,651	1,14,022	1,16,470

2.मानव विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 31.10.2025 तक 6,656 स्टेशनों पर बिंदुओं और संकेतों के केंद्रीकृत संचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए गए हैं

3.लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31.10.2025 तक 10,098 लेवल क्रॉसिंग गेटों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।

4.विद्युत माध्यम से ट्रैक की उपलब्धता की पुष्टि करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31.10.2025 तक 6,661 स्टेशनों पर पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था की गई है।

5.कवच एक अत्यंत तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली है। इसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। कवच को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रारंभ में, कवच संस्करण 3.2 को दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 आरकेएम और उत्तर मध्य रेलवे के 80 आरकेएम पर तैनात किया गया था। कवच विनिर्देश संस्करण 4.0 को आरडीएसओ द्वारा 16.07.2024 को मंजूरी दी गई थी। व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद, कवच संस्करण 4.0 को दिल्ली-मुंबई मार्ग पर पलवल-मथुरा-कोटा-नागदा खंड (633 किमी) और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर हावड़ा-बर्दवान खंड (105 किमी) पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्ग के शेष खंडों में कवच का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे के सभी जीक्यू, जीडी, एचडीएन और चिन्हित खंडों को कवर करते हुए 15,512 किमी पर कवच का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

6.सिग्नलिंग की सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों, जैसे अनिवार्य पत्राचार जांच, परिवर्तन कार्य प्रोटोकॉल, पूर्णता आरेखण तैयार करना आदि के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

7.एस एंड टी उपकरणों के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन की प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है।

8.सभी लोकोमोटिव में लोको पायलटों की सतर्कता बढ़ाने के लिए विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस (वीसीडी) लगाए गए हैं।

9.कोहरे के कारण कम दृश्यता होने पर चालक दल को आगे के सिग्नल के बारे में सूचित करने के लिए विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिग्नल से दो ओएचई मास्ट आगे स्थित मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए गए हैं।

10.लोको पायलटों को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट आदि जैसे निकटवर्ती स्थलों की दूरी का पता चल सके। इसके लिए कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों को जीपीएस आधारित कोहरे से सुरक्षा उपकरण (एफएसडी) प्रदान किया जाता है।

11.प्राथमिक ट्रैक नवीनीकरण के दौरान 60 किलोग्राम भार, 90 अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ (यूटीएस) रेल, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) नॉर्मल/वाइड बेस स्लीपर (इलास्टिक फास्टनिंग के साथ), पीएससी स्लीपरों पर फैन शेप्ड लेआउट टर्नआउट और गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपरों से युक्त आधुनिक ट्रैक संरचना का उपयोग किया जाता है।

12.मानवीय गलतियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी ट्रैक मशीनों के उपयोग के माध्यम से ट्रैक बिछाने की गतिविधि मशीनों से की जाती है।

13.रेल नवीनीकरण की प्रगति बढ़ाने और जोड़ों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे रेल पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना, जिससे सुरक्षा में सुधार हो सके।

14.रेलों में खामियों का पता लगाने और दोषपूर्ण रेलों को समय पर हटाने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन (यूएसएफडी) परीक्षण।

15.लंबी रेलों की बिछावट, एल्युमिनो थर्मिक वेल्डिंग का न्यूनतम उपयोग और रेलों के लिए बेहतर वेल्डिंग तकनीक, जैसे फ्लैश बट वेल्डिंग को अपनाना।

16.ओएमएस (ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम) और टीआरसी (ट्रैक रिकॉर्डिंग कार) द्वारा ट्रैक ज्यामिति की निगरानी।

17.वेल्ड/रेल फ्रैक्चर की जांच के लिए रेलवे ट्रैक पर गश्त।

18.टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।

19.कर्मचारियों को सुरक्षित प्रक्रियाओं के पालन के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण और प्रशिक्षण देना।

20.ट्रैक परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, जैसे ट्रैक डेटाबेस और निर्णय समर्थन प्रणाली, को तर्कसंगत रखरखाव आवश्यकताओं का निर्णय लेने और इनपुट को अनुकूलित करने के लिए अपनाया गया है।

21.एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्यस्थल सुरक्षा, मानसून के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां आदि ट्रैक की सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

22.रेलवे की संपत्तियों (कोच और वैगन) का निवारक रखरखाव सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

23.पारंपरिक आईसीएफ डिज़ाइन के कोचों को एलएचबी डिज़ाइन के कोचों से बदला जा रहा है।

24.ब्रॉड गेज (बीजी) रूट पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग (यूएमएलसी) जनवरी 2019 तक हटा दिए गए हैं।

25.रेलवे पुलों की सुरक्षा नियमित निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई स्थिति के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्वास की आवश्यकता पर विचार किया जाता है।

26.भारतीय रेल ने सभी कोचों में यात्रियों की व्यापक जानकारी के लिए वैधानिक "अग्नि सम्बंधी नोटिस" प्रदर्शित किए हैं। आग से बचाव के लिए विभिन्न नियमों और सावधानियों के बारे में यात्रियों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए प्रत्येक कोच में अग्नि सम्बंधी पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें ज्वलनशील सामग्री, विस्फोटक न ले जाने, कोच के अंदर धूम्रपान निषेध, जुर्माने आदि से सम्बंधित संदेश शामिल हैं।

27.उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैंट्री कारों में अग्नि पहचान एवं शमन प्रणाली तथा नवनिर्मित कोचों में अग्नि और धुआं पहचान प्रणाली उपलब्ध करा रही हैं। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा मौजूदा कोचों में भी चरणबद्ध तरीके से इन प्रणालियों को लगाने का कार्य प्रगति पर है।

28. कर्मचारियों का नियमित रूप से परामर्श एवं प्रशिक्षण किया जाता है।

29. भारतीय रेल (खुली लाइनें) के सामान्य नियमों में 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से रोलिंग ब्लॉक की अवधारणा को लागू किया गया है। इसके तहत परिसंपत्तियों के एकीकृत रखरखाव/मरम्मत/प्रतिस्थापन का कार्य 52 सप्ताह पहले तक रोलिंग आधार पर योजनाबद्ध किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।